Tribunals

भारत में पहला ट्रिब्यूनल (अधिकरण/न्यायाधिकरण)
आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल (1941)

हाईकोर्ट	ट्रिब्यूनल
संविधान द्वारा स्थापित	संविधान या कानून द्वारा स्थापित (केंद्र या राज्य)
सभी कानूनों का उपयोग	केवल विशिष्ट कानूनों का उपयोग
प्रक्रियाओं द्वारा बाध्य [जैसे CrPC]	नैसर्गिक (प्राकृतिक) न्याय (Natural justice) के सिद्धांत का पालन
केवल न्यायिक सदस्य	न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य
बिना वकील के केस कर सकते हैं? हाँ	बिना वकील के केस कर सकते हैं? हाँ

Polity class-5	pg-55
Timestamp हिंदी वीडियो	40:00
Timestamp English video	43:13

Polity class-6	pg-58
Timestamp हिंदी वीडियो	07:20
Timestamp English video	06:38

अनुच्छेद 227 *((Polity class-1 pg-2))*
प्रत्येक HC के पास अपने अधिकार क्षेत्र के सभी अदालतों और अधिकरणों पर अधीक्षण (Superintendence) होता है

- ❑ "आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल" के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? हाँ
- ❑ 'केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल' के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? हाँ

नोट: 'अनुच्छेद 227' मूल संरचना (Basic Structure) का हिस्सा है

Important *(PT365 Polity class-1 pg-2) (2022 Static class-7 and pg-47)*
मिलिट्री ट्रिब्यूनल/कोर्ट मार्शल के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है ? **हाँ**
मिलिट्री ट्रिब्यूनल/कोर्ट मार्शल के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition) दायर की जा सकती है ? **नहीं**

The Telegraph
NGT subordinate and can't contradict high courts: SC
Court quashed a Green Tribunal order that had stayed the construction of a resort by the Andhra Pradesh government on the Rushikonda Hills in Visakhapatnam
New Delhi | Published 02.06.22, 02:53 AM

THE HINDU
NGT fines Delhi govt. ₹2,232 crore for poor waste management
Tribunal also forms panel led by L-G to monitor waste management; it had earlier imposed ₹900-cr. fine on Delhi for 3 crore tonnes of waste
February 18, 2023 01:27 am | Updated 01:27 am IST – New Delhi

Hindustan Times
NGT, not Art of Living, should be fined for Yamuna floodplain damage: Sri Sri
Apr 19, 2017 11:03 AM IST
Art of Living founder Sri Sri Ravi Shankar on Tuesday said the Centre, Delhi government and the National Green Tribunal (NGT) should be held responsible for allowing his foundation to organise the World Culture Festival on the Yamuna floodplains in March 2016.

National Green Tribunal	
Environment class-4B	pg-45
Timestamp हिंदी वीडियो	47:50
Timestamp English video	47:26

NGT, WPA 1972 के तहत मामलों की सुनवाई कर सकता है? **नहीं**
NGT के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? **हाँ**
NGT हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील सुन सकता है? **नहीं**
NGT सरकार के साथ-साथ निजी संस्थाओं पर भी जुर्माना लगा सकता है? **हाँ**
NGT के आदेश बाध्यकारी हैं ? **हाँ** (NGT के पास सिविल कोर्ट जैसी शक्तियाँ होती हैं)

NGT में नियुक्तियां
अध्यक्ष : केंद्र द्वारा (CJI से परामर्श करके)
सदस्य : केंद्र द्वारा (चयन समिति की सिफारिश पर)

https://www.telegraphindia.com/india/ngt-subordinate-and-cant-contradict-high-courts-sc/cid/1867955

ऋषिकोंडा (रुशिकोंडा) पहाड़ियाँ
विशाखापत्तनम / विजाग (आंध्रप्रदेश) में स्थित
- ➢ इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क और कंबालाकोंडा वन्यजीव अभयारण्य के निकट

https://www.thenewsminute.com/article/ngt-pulls-telangana-govt-over-pollution-hyderabads-hussainsagar-form-panel-116641

हुसैन सागर झील
- ➢ दिल के आकार की झील तेलंगाना (हैदराबाद) में स्थित
- ➢ 1563 में इब्राहिम कुली कुतुब शाह द्वारा निर्माण
- ➢ मूसी नदी (कृष्णा की सहायक नदी) द्वारा पोषित

(कृष्णा नदी तेलंगाना-आंध्रप्रदेश की सीमा पर बहती है)

10वीं अनुसूची के तहत, स्पीकर ट्रिब्यूनल के रूप में कार्य करता है? हाँ

- स्पीकर न्यायिक शक्ति का प्रयोग करता है, लेकिन अदालती प्रक्रियाओं के बिना।
- इस तरह , 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का फैसला करते समय स्पीकर, ट्रिब्यूनल के रूप में कार्य करता है।
- चूँकि स्पीकर का चुनाव सत्तारूढ़ दल की इच्छानुसार होता है, इसलिए उसकी निष्पक्षता सुनिश्चित करना कठिन होता है।

District Judges

उच्च न्यायपालिका (SC/HC) में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम , (मई 2022 पत्रिका मैगज़ीन) देखे

अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति

❑ नियुक्ति/पोस्टिंग/पदोन्नति
- राज्यपाल द्वारा, हाई कोर्ट से परामर्श करके

❑ पात्रता
- केंद्र/राज्य की सेवा (Government Service) में ना हो
- कम से कम 7 साल तक अधिवक्ता (advocate) रह चुका हो
- हाई कोर्ट द्वारा अनुशंसित/सिफारिश की गयी हो

अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा (judicial service) में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती

राज्य PCS और हाई कोर्ट के परामर्श के बाद, राज्यपाल द्वारा (राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमानुसार)

अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों (subordinate courts) पर नियंत्रण

हाई कोर्ट का जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण होगा।

236. Interpretation.—In this Chapter—

(*a*) the expression "district judge" includes judge of a city civil court, additional district judge, joint district judge, assistant district judge, chief judge of a small cause court, chief presidency magistrate, additional chief presidency magistrate, sessions judge, additional sessions judge and assistant sessions Judge;

(*b*) the expression "judicial service" means a service consisting exclusively of persons intended to fill the post of district judge and other civil judicial posts inferior to the post of district judge.

Prelims 1996 भारत के संविधान के अनुसार 'जिला न्यायाधीश' में शामिल नहीं है :

(A) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(B) सत्र न्यायाधीश

(C) **<u>ट्रिब्यूनल न्यायाधीश</u>**

(D) लघु-वाद न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

District Judge

❑ जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है
- इनके आदेशों के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में होती है

❑ सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में मूल (Original) और अपीलीय (Apellate) क्षेत्राधिकार होते है
- जब वह सिविल मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश (District Judge) कहा जाता है
- जब वह आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश (Session Judge) कहा जाता है

❑ न्यायिक और प्रशासनिक दोनों शक्तियाँ होती हैं
- जिले के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर पर्यवेक्षी (Supervision) पावर होती हैं

❑ कोई भी सजा दे सकता है (मृत्युदंड भी दे सकता है)
- इनके द्वारा दी गई मृत्युदंड की सजा पर हाई कोर्ट की पुष्टि (Confirmation) होनी चाहिए , चाहे अपील हो या न हो

जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट

सिविल मामले → अधीनस्थ जज कोर्ट → मुंसिफ कोर्ट

आपराधिक मामले → मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट → न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट

अधीनस्थ जज कोर्ट: सिविल मामलो में असीमित आर्थिक क्षेत्राधिकार है

मुंसिफ कोर्ट: सीमित क्षेत्राधिकार है और छोटे आर्थिक हित के सिविल मामलों का निर्णय करता है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट: उन आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है जिनमें अधिकतम 7 साल की जेल हो सकती हो

न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट: उन आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है जिनमें अधिकतम 3 साल की जेल हो सकती हो

कुछ महानगरों में यह भी होता है -
- सिविल मामले में सिटी सिविल कोर्ट (मुख्य न्यायाधीश)
- आपराधिक मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट

संरचना/क्षेत्राधिकार/नामकरण हर राज्य में अलग-अलग होता है क्योंकि यह राज्यों द्वारा तय किया जाता है

ALL INCLUSIVE IAS

Bar & Bench

News | Columns | Interviews | Law Firms

Full Court of Supreme Court decides to begin live streaming of Constitution Bench hearings from September 27

Live-streaming

- 2022 : सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ की सुनवाई का लाइव-स्ट्रीमिंग शुरू किया
- 2021 : गुजरात HC औपचारिक रूप से अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला पहला HC था (अब कई HC ऐसा कर रहे हैं)
- 2018 : इंदिरा जयसिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय महत्व के मामलो की लाइव-स्ट्रीमिंग की अनुमति दी (स्वप्निल त्रिपाठी बनाम सुप्रीम कोर्ट केस)

2018 के फैसले के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य (Prelims लिए महत्वपूर्ण नहीं है)

- अनुच्छेद 129 SC को अदालती कार्यवाही प्रकाशित (Publish) करने का अधिकार देता है
- न्याय पाने का अधिकार (यह अनुच्छेद 21 से मिलता है) तभी सार्थक होगा जब जनता अदालती कार्यवाही देख सके
- धूप सबसे अच्छी कीटाणुनाशक है। लाइव-स्ट्रीमिंग, ओपन कोर्ट के विस्तार के रूप में, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएगी

कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड

- न्यायालय के निर्णय/कार्यवाही/कार्यो को सार्वकालिक अभिलेख (हमेशा के लिए) रखा जाता है
- उनका साक्ष्यीय महत्व है और किसी भी न्यायालय में उनकी प्रामाणिकता को चुनौती नहीं दी जा सकती
- उन्हें कानूनी मिसाल/विधिक सन्दर्भ (legal precedent) की तरह स्वीकार किया जाता है
- अवमानना (Contempt) के लिए दंडित करने की शक्ति है

अनुच्छेद 129 → SC अभिलेख न्यायालय (Court of Record) है

अनुच्छेद 215 → प्रत्येक HC एक अभिलेख न्यायालय (Court of Record) है

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

Explained: What is a full court meeting, called by the new Chief Justice of India soon after taking charge?

By: Explained Desk

New Delhi | Updated: August 30, 2022 10:56 IST NewsGuard

Full Court

संविधान/कानून/नियमों में परिभाषित ? **नहीं**

महत्वपूर्ण मामलों का फैसला कर सकती है ? **नहीं**

यह नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती है? **नहीं** (जब भी C.J.I. चाहें)

SC की प्रशासनिक प्रैक्टिसेज में संशोधन के लिए इसका निर्णय आवश्यक है? **नहीं**

परंपरा (Convention) के अनुसार CJI, सभी SC जजों को महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुलाते हैं ? **हाँ**

सुप्रीम कोर्ट के पूर्ण न्यायालय (Full Court) के कुछ फैसले

2022: संविधान पीठ की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होगी (2022 Static course class-7 pg-47)

2010: विधि आयोग (Law Commission) द्वारा क्षेत्रीय बेंच स्थापित करने के सुझाव को खारिज कर दिया (Polity class-6 pg-58)

1997: जजों को संपत्ति का खुलासा करना होगा। SC/HC जजों के लिए "इन-हाउस प्रक्रिया" अपनाई गई (Polity class-3 pg-28)

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

Why the Centre wants to revisit the process for designating senior advocates at Supreme Court, High Courts

Written by Khadija Khan

New Delhi | Updated: February 21, 2023 07:37 IST NewsGuard

Senior Advocate *वरिष्ठ अधिवक्ता*

वर्तमान प्रणाली

- स्थायी समिति Full Court को नाम भेजती है
- Full Court बहुमत से फैसला करता है
- Full Court पदनाम को वापस भी ले सकता है

स्थायी समिति के सदस्य

(a) CJI
(b) SC के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशश
(c) भारत के अटॉर्नी जनरल
(d) बार का सदस्य जिसे (a) से (c) द्वारा नामांकन

Background

- अधिवक्ता अधिनियम (Advocates Act) 1961: अधिवक्ताओं के दो वर्ग होंगे - वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता
- CJI द्वारा ऐसा पदनाम दिया जाता था, लेकिन प्रक्रिया अपारदर्शी थी
- 2015: इंदिरा जयसिंह (भारत की पहली महिला वरिष्ठ अधिवक्ता) ने अधिक पारदर्शिता के लिए जनहित याचिका दायर की
- 2017: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया
- 2018: सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की

ALL INCLUSIVE IAS

In-Camera

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE
What are in-camera proceedings, when are they conducted
Written by Omkar Gokhale
Mumbai | November 30, 2022 07:55 IST
NewsGuard

इन-कैमरा (बंद कमरा) कार्यवाही

- वे प्राइवेट में होती है, ओपन कोर्ट में नहीं होती
  - वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या बंद चैम्बर्स में होती है
  - जनता और प्रेस को बाहर रखा जाता है
  - मीडिया को मामले का प्रकाशन करने के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता होती है
- अदालत के विवेकानुसार आयोजित किए जाते हैं
  - पक्षकार इसकी मांग कर सकते हैं, या न्यायालय स्वयं आदेश दे सकते है
- संवेदनशील मामलों में की जाती है ताकि पार्टियों (पक्षों) की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके
  - रेप, POCSO, वैवाहिक विवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि
  - CrPC, POCSO एक्ट, Family Court Act आदि में उल्लेख किया गया है

In-camera proceedings | **Open Court** | **Live-streaming**

Language in Courts

Polity class-1	pg-9
Timestamp हिंदी वीडियो	01:14:43
Timestamp English video	01:04:33

- **सुप्रीम कोर्ट**
  - संविधान में अंग्रेजी भाषा का प्रावधान
  - संसद अन्य भाषाओं की अनुमति दे सकती है (लेकिन अभी तक ऐसा किया नहीं गया)
- **हाई कोर्ट**
  - संविधान में अंग्रेजी भाषा का प्रावधान
  - राज्यपाल अन्य भाषाओं की अनुमति दे सकते हैं
  - राजस्थान, MP, UP, बिहार में हिंदी भाषा की अनुमति दी जा चुकी है
- **अधीनस्थ न्यायालय (subordinate courts)**
  - HC और राज्य सरकार एक दूसरे से परामर्श करके निर्णय लेते है

Prelims के लिए निम्नलिखित Background important नहीं है

PIB 09-02-20233 https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1897702

- अनुच्छेद 348
  - सुप्रीम कोर्ट और प्रत्येक हाई कोर्ट में सभी कार्यवाही अंग्रेजी में होगी
  - राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, हाई कोर्ट की कार्यवाही में हिंदी या किसी अन्य भाषा के उपयोग की अनुमति दे सकते हैं (निर्णय, आज्ञप्ति, आदेश में नहीं)
- 1965 में कैबिनेट का फैसला
  - हाई कोर्ट में अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा के लिए CJI की सहमति लेनी होगी
- अनुच्छेद 235
  - हाई कोर्ट का जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ (subordinate) न्यायालयों पर नियंत्रण होगा
  - इसलिए निचली अदालतों में हिंदी या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल हाई कोर्ट और राज्य सरकार द्वारा एक दूसरे से परामर्श करके तय किया जाता है

---

https://doj.gov.in/use-of-hindi-and-regional-languages/

- राजस्थान, MP, UP, बिहार के हाई कोर्ट में कार्यवाही, निर्णय, आज्ञप्ति, आदेश के लिए बहुत पहले ही हिंदी के प्रयोग की अनुमति दी जा चुकी है।
- अन्य राज्य सरकारों ने भी हाई कोर्ट में स्थानीय भाषा के उपयोग की मांग की है ।
- 2012 में CJI ने बताया कि FULL COURT ने ऐसे प्रस्तावों को खारिज कर दिया है।
- 2014 में, TN सरकार के अनुरोध पर, केंद्र सरकार ने CJI से निर्णय की समीक्षा करने का अनुरोध किया।
- 2016 में, CJI ने बताया कि FULL COURT ने ऐसे प्रस्तावों को फिर से खारिज कर दिया है।

राजभाषा अधिनियम 1963 (Official Language Act 1963)

- इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई जिक्र नहीं है
- राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, हाई कोर्ट की कार्यवाही, निर्णय, आज्ञप्ति, आदेश में हिंदी या किसी अन्य भाषा की अनुमति दी जा सकती है

ICT in Courts

Polity class-6	pg-58
Timestamp हिंदी वीडियो	13:38
Timestamp English video	13:21

SC की e-Committee https://ecommitteesci.gov.in/

- ❑ न्यायपालिका में ICT पहल के लिए (ICT = सूचना और संचार प्रौद्योगिकी)
- ❑ यह "भारतीय न्यायपालिका में ICT के कार्यान्वयन के लिये राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना – 2005" के तहत e-Court परियोजना का पर्यवेक्षण (supervision) करती है
- ❑ e-Court की निगरानी और वित्त पोषण, न्याय विभाग (कानून और न्याय मंत्रालय) द्वारा किया जाता है।

e-Court परियोजना (PIB 22-07-2022 https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1843360)

- ❑ राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत 2007 में शुरू की गई
- ❑ इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय की पहुंच में सुधार करना है
- ❑ पहला चरण (2007-2015) : 14,249 न्यायालय स्थलों का कम्प्यूटरीकरण किया गया
- ❑ दूसरा चरण (2015 से) : अब तक 18,735 न्यायालय स्थलों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है
- ❑ Progress: (याद करने की जरूरत नहीं)
  - 99.3% अदालत परिसरों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड
  - Case Information Software विकसित किया गया है
  - राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, वकीलों और वादियों को मामले की स्थिति प्रदान करता है
  - यातायात नियमो के उल्लंघन्न के लिए 16 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 20 वर्चुअल कोर्ट
  - कुछ उच्च न्यायालयों में कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू।
  - वकालतनामा, e-हस्ताक्षर, शपथ, ऑनलाइन भुगतान आदि के लिए e-फाइलिंग प्रणाली शुरू की गई
  - हाई कोर्ट के फैसलों को ढूंढने के लिए 'जजमेंट एंड ऑर्डर सर्च' पोर्टल बनाया गया

Justice Clock
https://doj.gov.in/justice-clock/

- न्यायपालिका, योजनाओं आदि के बारे में जन जागरूकता बढ़ने के लिए।
- राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड से डेटा लेता है
- कई कई कोर्ट में लगाया गया है

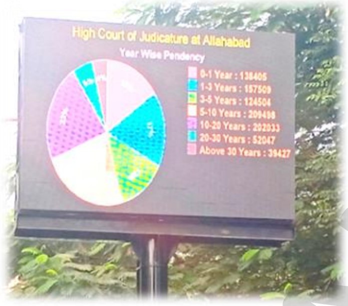

S3WAaS https://s3waas.gov.in/

- सेवा के रूप में सुरक्षित, स्केलेबल और सुगम्य वेबसाइट
- सरकारी संस्थाओं को वेबसाइट बनाने के लिए एक Cloud सेवा है
- यह कई थीम और कस्टमाइज़ेशन विकल्प देता है
- वेबसाइट को gov.in या nic.in डोमेन के तहत होस्ट किया जा सकता है

Prelims 2022 "सॉफ्टवेयर, सेवा के रूप में "Software as a Service(SaaS)" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. SaaS खरीदार उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस को अनुकूलित कर सकते हैं और डेटा फ़ील्ड बदल सकते हैं।
2. SaaS प्रयोक्ता मोबाइल डीवाईसेज से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं
3. Outlook, Hotmail और Yahoo! Mail SaaS के रूप हैं

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

DISHA डिजाइनिंग इनोवेटिव सोल्युशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस
(न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना)

- न्याय विभाग द्वारा, 2021-2026 के लिए
- इसका फोकस टेली-लॉ, प्रो बोनो लीगल सर्विसेज (न्याय बंधु), कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता पर है।

Also see: Polity क्लास-3 पेज -30 (हिंदी 1:38:50 , अंग्रेजी 1:25:58)

JustIS मोबाइल ऐप

- यह एक कोर्ट प्रबंधन उपकरण है
- यह न्यायाधीश को उसके कोर्ट के बारे में सभी विवरण देता है
- यह जिला और अधीनस्थ कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए है

ALL INCLUSIVE IAS

Prison/Jail

Polity class-6	pg-60
Timestamp हिंदी वीडियो	22:10
Timestamp English video	21:25

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)
- 1986, मुख्यालय-दिल्ली
- गृह मंत्रालय
- अपराधों, अपराधियों, फिंगरप्रिंट्स आदि का डेटाबेस बनाए रखता है।

NCRB की रिपोर्टस
- Crime in India
- Fingerprint in India
- Missing Women & Children
- Accidental deaths & Suicides
- Prison Statistics

the quint
Become a Member

8 in 10 Prisoners Await Trial as India's Inmate Population Grows: Govt Data

VIRAJ GAUR
INDIA
Published: 14 Sep 2022, 1:36 PM IST
3 min read

Prison Statistics India रिपोर्ट
- पहली बार प्रकाशन 1995, नवीनतम 2021
- यह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के जेल-मुख्यालयों से डेटा लेता है
- यह एकमात्र वार्षिक Statistics रिपोर्ट है जो NCRB द्वारा शुरू की गई (अन्य रिपोर्टस NCRB के गठन से पहले शुरू जो गई थी)

जेल (भारत में)

जेलों की संख्या	1319
अधिकांश सेंट्रल जेल	दिल्ली (14)
अधिकांश जिला कारागार (जेल)	UP (62)
सबसे ज्यादा जेल	राजस्थान (144) तमिलनाडु (142)

कैदी (भारत में)

जेलों की क्षमता	4.25 लाख
जेलों में बंद लोग (कैदी)	5.5 लाख (130% Occupancy Rate)
विचाराधीन (undertrials)	4.3 लाख (कुल कैदियों का 78%)
अधिकांश कैदी	UP में (1.2 लाख) बिहार में (67,000)

नोट :
- कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों कोई सेंट्रल जेल या जिला जेल नहीं है
- केवल 15 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में महिला जेलें हैं (~6700 की क्षमता वाली कुल 32 महिला जेलें हैं)

क्या आपको पता था?
अरुणाचल प्रदेश में पहली जेल 2009 में बनी (उससे पहले पुलिस लॉकअप का इस्तेमाल किया जाता था)

सरकार की कुछ पहल *(गृह मंत्रालय इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्यों के साथ काम करता है)*
- **ई-जेल** → जेलों के कामकाज का कम्प्यूटरीकरण आदि।
- **मॉडल प्रिज़न मैनुअल** → 'जेल प्रशासन' पर राज्यों का मार्गदर्शन करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा 2016 में प्रकाशित
- **जेलों का आधुनिकीकरण** → सुरक्षा-ढांचा, सुधार, पुनर्वास आदि को मजबूत करने के लिए 2021-2026 के दौरान सहायता-अनुदान (Grant-in-aid) के रूप में केंद्र द्वारा धनराशि प्रदान की जाएगी

ALL INCLUSIVE IAS